



## संचार मंत्री का संदेश — दूरसंचार विभाग

### नमस्कार!

भारत का दूरसंचार क्षेत्र सुरक्षित, समावेशी और भविष्य-केन्द्रित डिजिटल इकोसिस्टम के स्पष्ट विज़न के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। पिछले एक महीने में, दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंफ्रा को सुदृढ़ बनाने, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और देशभर में नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करने को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़त को 'भारत 6जी अलायंस' में हुई उल्लेखनीय प्रगति और 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' के तहत राष्ट्रीय अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयासों से और बल मिला है। ये प्रयास भारत को वैश्विक 6जी विकास और इनोवेशन में सबसे आगे रखने के हमारे पक्के इरादे को दर्शाते हैं।

सी-डॉट द्वारा दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षित, टेक्नोलॉजी-आधारित स्मार्ट पुलिसिंग समाधान विकसित करने के लिए किए गए सहयोग से स्वदेशी अनुसंधान और विकास को और बढ़ावा मिला है। यह पहल शासन और सार्वजनिक सुरक्षा में टेलीकॉम इनोवेशन की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है और यह सुनिश्चित करती है कि टेक्नोलॉजी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' के रूप में काम करे।

हमारा ध्यान दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने पर बना हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में नेटवर्क से संबंधित 'क्वालिटी ऑफ़ सर्विस' के निर्धारित मानकों को पूरा किया है। इससे नागरिकों के लिए भरोसेमंद और लगातार कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है।

किफायती ब्रॉडबैंड की पहुंच का विस्तार करना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पीएम-वाणी योजना के तहत, 4 लाख से अधिक पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं, जिससे 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' में अत्यधिक तेज़ी आई है, शहरी तथा ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिला है। डिजिटल शासन से जुड़ी पहलों को भी और गति मिली है। गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी द्वारा 'संपन्न' प्लेटफॉर्म को अपनाना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को दर्शाता है।

डॉट ने टेलीकॉम से जुड़े वित्तीय घोटालों और निवेश संबंधी धोखाधड़ी में टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए सेबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। "सभी के लिए कनेक्टिविटी" के अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए, दूरसंचार विभाग ने उभरती हुई 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' टेक्नोलॉजी पर महत्वपूर्ण चर्चाओं की सुविधा प्रदान की। इन चर्चाओं में वैश्विक विशेषज्ञ और हितधारक एक साथ आए, ताकि ऐसे अभिनव सैटेलाइट संचार समाधानों का पता लगाया जा सके जो सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर सकें। भारत के डिजिटल और वित्तीय इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। भारत का स्वदेशी इनोवेशन इकोसिस्टम लगातार और मजबूत होता जा रहा है। सी-डॉट ने अपने 'बौद्धिक संपदा' (आईपी) पोर्टफोलियो का विस्तार किया है और अपने वार्षिक आईपी पुरस्कारों के माध्यम से इनोवेटर्स को सम्मानित किया है। इससे अत्याधुनिक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहन मिला है।

समावेशी ग्रामीण डिजिटल बदलाव की दिशा में हमारे प्रयासों को वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिली है। भारत नेट द्वारा समर्थित 'समृद्ध ग्राम' पहल को प्रतिष्ठित डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। यह नामांकन डिजिटल खाई को पाटने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में इस पहल के प्रभाव को रेखांकित करता है।

इसके साथ ही, साइबर सुरक्षा जागरूकता को सुदृढ़ करने के प्रयासों को भी बल मिला है; सी-डॉट और जंप्स ऑटोमेशन एलएलपी के बीच हुए समझौते के माध्यम से एक 'गेमीफाइड' प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और उद्यमों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसे गतिशील दूरसंचार इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग बनी हुई है, जो प्रत्येक नागरिक को जोड़े, प्रत्येक उद्यम को सशक्त बनाए और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भारत की स्थिति वैश्विक तौर पर एक अग्रणी देश के रूप में सुरक्षित करे।

जय हिंद

आपका,

**ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया**

संचार मंत्री, भारत सरकार